

## बिहार में बैंकिंग अधिसंरचना : एक अवलोकन

\*हेमा कुमारी

शोधार्थी

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग  
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार

\*\*डॉ० श्याम चन्द्र गुप्ता

एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रधानाचार्य  
एम.आर.एम. कॉलेज, दरभंगा, बिहार

### सार संक्षेप

बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण मिलना बिहार समेत किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अधिसंरचना सबसे व्यापक है, जिसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थान है। राज्य में निजी क्षेत्र के बैंकों और लघु बचत बैंकों की उपस्थिति क्रमिक रूप से बढ़ी है। बिहार में बैंकों के लिए वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) का लक्ष्य 2020-21 में 1.54 लाख करोड़ रु. से बढ़कर 2021-22 में 1.62 लाख रु. हो गया। लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि के प्रतिशत में भी सुधार हुआ है, जो 2020-21 के 82.8 प्रतिशत से बढ़ कर 2021-22 में 99.6 प्रतिशत हो गया। राज्य में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में अनिष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का हिस्सा भी 2021-22 में पिछले साल से घटा है। राज्य में होने वाले कुल जमा में सर्वाधिक हिस्सा वाले अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 44.2 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत (72.1 प्रतिशत) से काफी नीचे है। इसलिए आवश्यक है कि बिहार में जमा राशि जुटाने के लिहाज से सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक को अपने वर्तमान ऋण-जमा अनुपात (36.1 प्रतिशत) में सुधार करना चाहिए। असेवित क्षेत्रों में आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों ने राज्य में आउटसोर्स किए गए ग्राहक सेवा केंद्रों (सीएसपी) की संख्या बढ़ाई है। लेकिन ऋण बैंक शाखाओं द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, ग्राहक सेवा केंद्रों द्वारा नहीं। इसलिए राज्य में बैंकिंग अधिसंरचना का विस्तार करने की जरूरत है क्योंकि देश की कुल बैंक शाखाओं में बिहार का हिस्सा जनसंख्या में राज्य के हिस्से की तुलना में काफी कम है।

### भूमिका

विगत वर्षों के दौरान बिहार की अर्थव्यवस्था के सतत विकास के कारण औपचारिक वित्तीय स्रोतों से ऋण उपलब्ध कराने की जरूरत बढ़ गई है। इसलिए राज्य की अर्थव्यवस्था के और अधिक विकास के लिए बैंकिंग संस्थानों को भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे औपचारिक वित्तीय संस्थानों से उचित व्यय पर उच्चस्तरीय वित्तीय पूंजी को उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

हाल में प्रौद्योगिकियों के हुए उन्नयन के कारण व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा वित्तीय लेनदेन करने का तरीका बदल गया है। जैसे, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल आधारित वित्तीय लेनदेन में वृद्धि हुई है। इनमें मोबाइल बैंकिंग और यूपीआइ (एकीकृत भुगतान इंटरफेस) आधारित लेनदेन शामिल हैं। इसके कारण औपचारिक वित्तीय संस्थानों तक लोगों की पहुंच में सुधार हुआ है। साथ ही, बैंक-रहित इलाकों में कुछ बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंकों ने ग्राहक सेवा केंद्रों (सीएसपी) या बैंक मित्रों को आवश्यक बैंकिंग सेवाएं आउटसोर्स भी किए हैं। लेकिन ऋण पाने के लिए ऋण लेने वालों का बैंक शाखाओं में जाना पड़ता है। इसलिए बिहार के बैंक-रहित क्षेत्रों में भौतिक बैंकिंग अधिसंरचना का विस्तार करने की जरूरत है।

### बिहार में बैंकिंग सुविधाएं

लोगों के रोजमर्रे के क्रियाकलापों में बैंकों की संलग्नता बढ़ने के साथ बैंकिंग अधिसंरचना में सुधार की मांग भी बढ़ी है। आधुनिक बैंकिंग और वित्तीय संस्थान भौतिक और डिजिटल, दोनों प्रकार की अधिसंरचनाओं का उपयोग करके अपनी सेवाएं देते हैं। बैंक शाखाएं, एटीएम (स्वचालित टेलर मशीन), ग्राहक सेवा केंद्र आदि अधिसंरचनाएं नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में आवश्यक भूमिका निभाती हैं। साथ ही, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआइ भुगतान प्रणालियां इंटरनेट और मोबाइल पर आधारित डिजिटल अधिसंरचना का उपयोग करती हैं।

बिहार में बैंकिंग अधिसंरचना का सारांश तालिका 1 में प्रस्तुत है। 31 मार्च, 2022 तक बिहार में 7713 बैंक शाखाएं थीं जो 31 मार्च, 2021 की 7676 शाखाओं से 1 प्रतिशत अधिक है। 5083 शाखाओं वाले व्यावसायिक बैंकों का बैंकिंग नेटवर्क राज्य में सबसे व्यापक है जिसके बाद 2110 शाखाओं वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थान है (तालिका 2)। साथ ही, राज्य में एटीएम की संख्या भी बढ़ी है जो 31 मार्च, 2021 के 6608 से 2 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च, 2022 को 6744 हो गई। इस दौरान डिजिटल बैंकिंग अधिसंरचना का उपयोग भी बढ़ा है। इंटरनेट बैंकिंग के उपयोगकर्ताओं की संख्या 31 मार्च, 2021 से 31 मार्च, 2022 के बीच 40.5 प्रतिशत बढ़ी है। इस अवधि में मोबाइल बैंकिंग के उपयोगकर्ताओं की संख्या 112.4 प्रतिशत बढ़ गई। वहीं, 31 मार्च, 2021 से 31 मार्च, 2022 के बीच पॉस (पाइंट ऑफ सेल विक्रय केंद्र) मशीनों की संख्या 48.3 प्रतिशत और एटीएम कार्डों की संख्या 12.2 प्रतिशत बढ़ी।

**तालिका 1 : बिहार में बैंकिंग सुविधाएं**

	बैंक शाखाएं	ग्राहक सेवा केंद्र	एटीएम	पॉस	इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग (लाख में)	मोबाइल बैंकिंग का उपयोग (लाख में)	एटीएम कार्ड (लाख में)
31 मार्च, 2022 को	7713	40,482	6944	86,489	102.33	131.75	729.13
31 मार्च, 2021 को	7676	31,095	6608	58,331	72.8	62.0	650.0
प्रतिशत परिवर्तन	Neg.	30.2	2.0	48.3	40.5	112.4	12.2

नोट: पॉस पाइंट ऑफ सेल विक्रय केंद्र  
**स्रोत: राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट**

सुदूर क्षेत्रों में बैंकिंग कार्यों के ढांचे में एक बुनियादी बदलाव बैंकों द्वारा ग्राहक सेवा केंद्रों का विस्तार है। ये बैंकिंग आउटलेट होते हैं जहां आउटसोर्स किए गए अभिकर्ताओं द्वारा सीमित बैंकिंग क्रियाकलाप चलाए जाते हैं। ग्राहक वहां से रकम निकाल सकते हैं या वहां रकम जमा कर सकते हैं। बिहार में ग्राहक सेवा केंद्रों की संख्या गत वर्ष से 30.2 प्रतिशत बढ़कर मार्च, 2022 के अंत में 40,822 हो गई (तालिका 1) इन केंद्रों से पारंपरिक बैंक शाखाओं के काम का बोझ घटाने और बड़ी आबादी को कम खर्च में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिली है। तालिका 2 में बिहार को बैंकों द्वारा बनाए गए ग्राहक सेवा केंद्रों वा बैंक मित्रों की संख्या दर्शाई गई है। व्यावसायिक बैंकों ने 31 मार्च, 2021 से 31 मार्च, 2022 के बीच ग्राहक सेवा केंद्रों की संख्या 72.0 प्रतिशत बढ़ाकर बैंक मित्रों की संलग्नता बढ़ाई है। 31 मार्च, 2022 को इन बैंकों के 25,769 ग्राहक सेवा केंद्र थे। वहीं, 31 मार्च, 2022 तक इंडिया पोस्ट के भुगतान बैंक ने 9015 और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 5679 बैंक मित्रों को काम में लगाया है।

**तालिका 2 : बिहार में विभिन्न बैंकों द्वारा तैनात ग्राहक सेवा केंद्रों या बैंक मित्रों की संख्या**

बैंक	31 मार्च, 2021 को		31 मार्च, 2022 को		प्रतिशत वृद्धि	
	शाखाओं की सं.	कार्यरत ग्राहक सेवा केंद्रों की सं.	शाखाओं की सं.	कार्यरत ग्राहक सेवा केंद्रों की सं.	शाखाओं की सं.	कार्यरत ग्राहक सेवा केंद्रों की सं.
व्यावसायिक बैंक	5082	14,986	5083	25,769	neg	72.0
सहकारी बैंक	286	0	289	0	neg	—
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2110	5671	2110	5679	0.0	01
लघुवित्त बैंक	198	14	211	19	16.7	35.7
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक	—	10,424	—	9015	—	(-) 13.5
<b>योगफल</b>	<b>7676</b>	<b>31,095</b>	<b>7713</b>	<b>40,482</b>	<b>neg</b>	<b>30.2</b>

**स्रोत: राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट**

तालिका 3 में बिहार में 2017-18 से 2021-22 तक बिहार में विभिन्न बैंकों द्वारा खुली नई बैंक शाखाओं की संख्या दर्शाई गई है। वर्ष 2021-22 में बिहार में कुल 129 नई बैंक शाखाएं खुलीं जो 2020-21 में खुली 270 नई शाखाओं से कम है। भारतीय स्टेट बैंक ने 11 और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कुल 35 नई शाखाएं शुरू की। वहीं, 2021-22 में निजी क्षेत्र के बैंकों की 24 और लघुवित्त बैंकों की 59 नई शाखाएं खुली।

**तालिका 3 : बिहार में खुली बैंकों की नई शाखाएं (2018-19 से 2021-22)**

वर्ष	भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी	राष्ट्रीयकृत बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	लघुवित्त बैंक	भुगतान बैंक	सभी बैंक
2018-19	1	17	1	57	107	38	221
2019-20	17	31	—	110	17	2	177
2020-21	115	52	1	92	9	1	270
2021-22	11	35	—	24	59	—	129

स्रोत : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के जमा और ऋण पर त्रैमासिक सांख्यिकी, भारतीय रिजर्व बैंक

वर्ष 2020-21 और 2021-22 में खोली गई नई शाखाओं का क्षेत्रवार वितरण तालिका 4 में प्रस्तुत है। वर्ष 2021-22 में नई खुली शाखाओं में से 41.9 प्रतिशत अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 31.8 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में खुलीं। शेष 17.1 प्रतिशत नई शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खुलीं। बैंकों ने अपनी अधिकांश शाखाएं शहरी या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोली हैं इसलिए कुल नई शाखाओं में ग्रामीण क्षेत्रों का हिस्सा बहुत कम है। इसका आंशिक कारण इन क्षेत्रों में जरूरी बैंकिंग सेवाएं देने में ग्राहक सेवा केंद्रों की बड़ी भूमिका है।

**तालिका 4: बैंकों की नई शाखाओं का क्षेत्रवार वितरण (2020-21 और 2021-22)**

क्षेत्र	2020-21		2021-22	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
ग्रामीण	59	21.9	22	17.1
अर्ध-शहरी	63	23.3	54	41.9
शहरी	117	43.3	41	31.8
महानगर	31	11.5	12	9.3
<b>योगफल</b>	<b>270</b>	<b>100.0</b>	<b>129</b>	<b>100.0</b>

स्रोत: अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के जमा और ऋण पर त्रैमासिक सांख्यिकी, भारतीय रिजर्व बैंक

तालिका 5 में बैंक समूहों के अनुसार बैंक शाखाओं की संख्या प्रस्तुत है। बैंकों को इन समूहों में बांटा जा सकता है भारतीय स्टेट बैंक, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, लघुवित्त बैंक और भुगतान बैंक। वर्ष 2021 और 2022 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं की संख्या लगभग समान ही रही। दूसरी ओर, राज्य में बैंक शाखाओं के नेटवर्क में निजी बैंक और लघुवित्त

बैंकों का हिस्सा बढ़ा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या भी हाल के वर्षों में समान रही और उनकी कोई नई शाखा नहीं खुली। वहीं, भुगतान बैंकों की शाखाओं की संख्या 2020 में 71 थी जो सितंबर 2022 में 59 रह गई। उनकी शाखाओं में कमी का कारण कामकाज का तरीका हो सकता है जो मुख्यतः ऑनलाइन या मोबाइल नेटवर्क के जरिए होता है। वहीं, वर्ष 2022-23 में सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की नई 6 शाखाएं और निजी क्षेत्र के बैंकों की 13 शाखाएं शुरू हुईं। राज्य में लघुवित्त बैंकों की शाखाओं के नेटवर्क का काफी विस्तार हुआ और शाखाओं की संख्या मार्च 2020 के 182 से बढ़कर सितंबर 2022 में 287 हो गई। बिहार में विदेशी बैंक की एक ही शाखा है जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की पटना शाखा है।

**तालिका 5 : बिहार में कार्यशील बैंक शाखाओं का बैंक समूह-वार वितरण (मार्च 2020 से सितंबर 2022)**

बैंक समूह	मार्च 2020	मार्च 2021	मार्च 2022	सितंबर 2023
भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी	1023 (13.5)	1117 (14.4)	1092 (14.0)	1095 (13.9)
राष्ट्रीयकृत बैंक	3143 (41.3)	3123 (40.2)	3102 (39.8)	3105 (39.5)
विदेशी बैंक	1 (नगण्य)	1 (नगण्य)	1 (नगण्य)	1 (नगण्य)
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2137 (28.1)	2138 (27.5)	2138 (27.4)	2138 (27.2)
निजी क्षेत्र के बैंक	1047 (13.8)	1138 (14.6)	1161 (14.9)	1174 (14.9)
लघुवित्त बैंक	182 (24)	191 (2.5)	250 (3.2)	287 (3.7)
भुगतान बैंक	71 (0.9)	62 (0.8)	59 (0.8)	59 (0.8)
योगफल	7803 (100.0)	7859 (100.0)	7604 (100.0)	7770 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत वितरण हैं।

#### स्रोत : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के जमा और ऋण पर त्रैमासिक सांख्यिकी, भारतीय रिजर्व बैंक

वर्ष 2007 से और 2022 के बीच देश के बड़े राज्यों में बैंकों की शाखाओं का नेटवर्क तालिका 6 में प्रस्तुत है। संपूर्ण भारत के बैंक शाखाओं के नेटवर्क में बिहार का हिस्सा 2007 के 4.9 प्रतिशत से घटकर 2017 में 4.6 रह गया था जो बाद में थोड़ा बढ़ा और 2022 में 5.0 प्रतिशत हो गया। लेकिन देश की बैंक शाखाओं की कुल संख्या में बिहार का हिस्सा जनसंख्या में इसके 8.6 प्रतिशत अनुपात के लिहाज से काफी कम है। देश की कुल बैंक शाखाओं में बिहार के कम हिस्से से पता चलता है कि बिहार में प्रति बैंक शाखा लोगों की संख्या देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। हालांकि बैंकिंग के कुछ क्रियाकलाप बैंक शाखाओं के अस्तित्व पर पूर्णतः निर्भर नहीं हैं और मोबाइल बैंकिंग (एटीएम और ग्राहक सेवा केंद्रों) के जरिए भी चल सकते हैं लेकिन राज्य में बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार किया जाना जरूरी है।

तालिका 6: व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं का राज्यों के अनुसार प्रतिशत वितरण

राज्य	मार्च 2007	मार्च 2012	मार्च 2017	मार्च 2022
असम	2.0	1.8	1.6	1.8
<b>बिहार</b>	<b>4.9</b>	<b>4.8</b>	<b>4.6</b>	<b>5.0</b>
छत्तीसगढ़	1.9	1.8	1.6	1.5
गुजरात	5.6	5.3	5.4	5.2
हरियाणा	3.3	3.4	3.0	2.6
हिमाचल प्रदेश	1.1	1.1	1.2	1.2
झारखंड	2.1	2.1	2.2	2.1
कर्नाटक	6.9	7.2	7.2	7.3
केरल	4.4	4.5	5.0	5.2
मध्य प्रदेश	4.8	4.6	4.7	4.9
महाराष्ट्र	8.9	8.9	9.5	9.5
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	2.4	2.6	2.8	2.7
ओडिशा	3.5	3.4	3.3	3.4
पंजाब	4.2	4.5	4.3	4.1
राजस्थान	5.2	5.0	4.8	5.0
तमिलनाडु	7.8	7.5	7.6	7.3
तेलंगाना	3.7	3.6	3.7	3.4
उत्तराखंड	1.4	1.4	1.4	1.3
उत्तर प्रदेश	11.6	11.9	12.0	12.0
पश्चिम बंगाल	6.2	6.1	6.1	6.5
<b>संपूर्ण भारत</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

स्रोत : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के जमा और ऋण पर त्रैमासिक सांख्यिकी, भारतीय रिजर्व बैंक

### बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की अपेक्षाकृत कम उपस्थिति वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं देने में अनिवार्य भूमिका निभाते हैं। राज्य में इनके विशाल नेटवर्क से मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं सीमांत किसानों, कारीगरों और समाज के वित्तीय रूप से कमजोर तबके के लोगों को ऋण पाने में मदद मिलती है। बिहार में दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं—दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। बिहार में दोनों बैंकों की शाखाओं की संख्या तालिका 7 में दर्शाई गई है।

बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 68.8 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 26.2 प्रतिशत अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 5.0 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में हैं। इनमें से दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की 75.4 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। वहीं, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की 61.9 प्रतिशत शाखाएं ही ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। बिहार के दोनो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या सितंबर 2021 और सितंबर 2022

में बराबर हो रही हैं। लेकिन दोनो बैंकों द्वारा जारी एटीएम कार्डों की संख्या सितंबर 2021 के 33.1 लाख से बढ़कर सितंबर 2022 में 33.6 लाख हो गई। अपने शाखा नेटवर्क के अलावा, नकद रकम की निकासी सहित कुछ जरूरी बैंकिंग सेवाएं देने के लिए ये बैंक ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से भी काम करते हैं। सितंबर 2021 में राज्य में ग्रामीण बैंकों के 5679 ग्राहक सेवा केंद्र काम कर रहे थे।

### तालिका 7 : बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या (सितंबर 2022)

बैंक का नाम	शाखाओं की अवस्थिति				एटीएम कार्ड (लाख में)
	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	योगफल	
दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक	813 (75.4)	204 (18.9)	61 (57)	1078 (100.0)	22.3
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	639 (61.9)	349 (33.8)	44 (4.3)	1032 (100.0)	11.3
योगफल	1452 (68.8)	553 (26.2)	105 (5.0)	2110 (100.0)	33.6

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत वितरण हैं।

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

### निष्कर्ष

अनुसूचित व्यावसायिक बैंक बिहार सहित पूरे देश में जमाराशि इकट्ठा करने में अनिवार्य भूमिका निभाते हैं। ये बैंकिंग संस्थान व्यक्तियों तथा उद्योगों के लिए मुख्य ऋणदाता भी हैं। ये बैंक अर्थव्यवस्था में बैंकिंग लेनदेन के मुख्य सुगमकर्ता हैं। बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के बैंकिंग नेटवर्क में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वर्चस्व है। सार्वजनिक क्षेत्र के बीच भारतीय स्टेट बैंक का बिहार में सबसे विस्तृत नेटवर्क है और बैंक आधारित लेनदेन में उसका अच्छा-खासा हिस्सा है। राज्य में निजी क्षेत्र के बैंकों की संख्या भी क्रमशः बढ़ी है। उनकी शाखाओं में भी क्रमिक लेकिन निरंतर वृद्धि हुई है। लघुवित्त बैंकों की शाखाओं की संख्या भी बढ़ी है। दोनो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी राज्य में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में आवश्यक भूमिका निभाते हैं।

वितरण के पैटर्न में बिहार और भारत के बीच काफी भिन्नता है। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की कुल शाखाओं में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों का हिस्सा पूरे देश में लगभग 60 प्रतिशत है जो बिहार में 75 प्रतिशत है। इसका मुख्य कारण यह है कि बिहार की एक बड़ी आबादी ग्रामीण अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहती है। जहां तक शहरी क्षेत्रों और महानगरों में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं की कुल संख्या की बात है, तो राष्ट्रीय स्तर पर यह लगभग 40 प्रतिशत है लेकिन बिहार में 25 प्रतिशत से भी कम है। बैंकिंग अधिसंरचना में बदलाव आने से एटीएम और एटीएम कार्डों की भूमिका बढ़ी है क्योंकि नकद निकासी के मामले में वे चौबीसों घंटे सेवा प्रदान करते हैं। बैंकों के चुनिंदा एटीएम आउटलेट में तो चौबीसों घंटे नकद रकम जमा भी की जा सकती है। मोबाइल नंबर अपडेट करना, एटीएम का पिन बदलना और रकम के

अंतरण जैसे अन्य बैंकिंग क्रियाकलाप भी एटीएम का उपयोग करके किए जा सकते हैं। प्रौद्योगिकी आधारित इन विकासों से नकद रकम की सहज उपलब्धता में सुधार हुआ है और नकद रकम निकालने के लिए बैंकों की शाखाओं में जाने वाले लोगों की संख्या घटी है। अगर एटीएम के कामकाज का सही-सही उपयोग किया जाय और वित्तीय धोखाधड़ी को नियंत्रित किया जाय तो इन सुविधाओं का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। नकद रकम निकालने के लिए एटीएम पर बड़ी निर्भरता के कारण एटीएम अधिसंरचना का विस्तार जरूरी हो जाता है। साथ ही, एटीएम सुविधाओं का उचित प्रबंधन होना चाहिए ताकि एटीएम के अंदर लंबी लाइन नहीं लगे और 'नकद उपलब्ध नहीं' का संदेश कम से कम देखना पड़े।

**सन्दर्भ :**

1. आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21
3. पंत, नवीन (2010), ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ, योजना, वर्ष 54, अंक 2, फरवरी, पृष्ठ 13-17.
4. प्रसाद, जगदीश (2000), नव बिहार : एक भविष्य निरूपण, तन्या प्रेस, पटना
5. बिहार राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट
6. यादव, चंद्रभान (2010), बैंकों से बदलती गांवों की तस्वीर, योजना, वर्ष 54, अंक 2, फरवरी, पृष्ठ 42
7. [www.bih.nic.in](http://www.bih.nic.in)
- 8- [www.nabard.org.in](http://www.nabard.org.in)
9. [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)